

असाधार्ग EXTRAORDINARY

भाग II—कुण्ड 3—उप-खण्ड (il) PART II—Section 3—Sub-Section (il)

भाषिकार सं प्रकृतित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575] नई दिल्ली, मंगलबार, स्नितम्बर 28, 1993/आधिवम 6, 1915 No. 575] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 1993/ASVINA 6, 1915

गृह मंत्रालय

मधिसूचना

नई विल्ली, 28 सितम्बर, 1993

का.ग्रा. 722(म्र):—यतः सा.का.नि. संख्या 804(म्र), दिनांक 4 दिसम्बर, 1984 के तहत भारत सरकार, गृह मंत्रालय की म्रधिसूचना के म्रत्नगैन, प्रातंकवाद से प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) म्रधिनियम, 1984 (1984 का 61) की धारा 4 के म्रधीन चंडीगढ़ न्यायिक जोन के संबंध में म्रजभेर, राजस्थान राज्य में एक म्रिनियन विशेष न्यायालय का गठन किया गया था;

और यक्तः चंडीगढ़ न्यायिक जोन क्षेत्र श्रव श्रातंकवाद से प्रभावित क्षेत्र नहीं रहा है ; और यत: भारत सरकार, गृह मंत्रालय की श्रश्चिम्चना सं. का.श्रा. 695(श्र), विनांक 25 सितम्बर, 1985 के तहत चंडीगढ़ न्यायिक जोन के संबंध में विशेष न्यायालय को पहले ही समाप्त कर दिया गया है;

भीर यतः म्नितिस्त विशेष न्यायालय, भ्रजमेर में कोई मामला लिम्बित नहीं है; भतः, ग्रब, भातंकवाद से प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) म्निवित्यम, 1984 (1984 का 61) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना के अयोग गठित नडोगढ़ न्यायिक क्षेत्र के विये में भजमेर स्थित मृतिस्ति विशेष न्यायाजय का 30 सितस्यर, 1993 सुसमान्त करती है।

> [फा.सं. 1/12/84-लीगल सैंल] सी.डी. श्राढा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th Scptember, 1993

S.O. 722(E).—Whereas an Additional Special Court in relation to the judicial zone of Chandigarh was established under section 4 of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984 (61 of 1984) under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs vide G.S.R. No. 804(E) dated the 4th December, 1984 at Ajmer in the State of Rajas han;

And whereas the area comprising the judicial zone of Chandigarh has censed to be a terrorist affected area,

And whereas the Special Court in relation to the judicial zone of Chandigarh has already been abolished vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, No. S.O. 695(E), dated the 25th September, 1985;

And whereas no case is pending in the Additional Special Court at Ajmer;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 15-A of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984 (61 of 1984), the Central Government hereby abolishes, with effect from the 30th September, 1993, the Additional Special Court at Ajmer in relation to judicial zone of Chandigarh as established under the said notification.

[File No. 1|12|84-Legal Cell]C. D. ARHA, Jt. Secy.